देश में फिर लौटा **कोरोना**

उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा 'ऑपरेशन सिंदूर'

# दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 01 | मूल्य 15 रुपये | 25-31 मई, 2025

## उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तस्वीर साफ

EXPERIENCE HELI TOUR WITH

Himgiri
Aviation & Tourism

**3N/4D TOUR**

# Do Dham

## YATRA BY HELICOPTOR

**LIMITED SEATS ARE LEFT** **BOOK NOW**


**Contact for Reservation** **8433456398, 9410353164**

Email: himgiritourism@gmail.com

6 Municipal Road, Opps. Bala hissar Academy, Dalanwala, Dehradun-248001 (UK)

वर्ष 15 | अंक 01

# दिव्य हिमगिरि

25-31 मई, 2025

**संपादक**
कुँवर राज अस्थाना

**वरिष्ठ संवाददाता**
शंभूनाथ गौतम

**ब्यूरो प्रमुख**
मोनिका डबराल

**विज्ञापन**
पूनम आर्या

**ग्राफिक डिजायनर**
देव भट्ट

**संवाददाता**
**हरिद्वार :** डॉ. रजनीश गौतम
**पौडी :** रत्नमणि भट्ट
**कोटद्वार :** के.पी. बौंठियाल
**रूद्रपुर :** हेमचन्द्र बुडलाकोटी
**चमोली :** मुकेश रावत
**रुड़की :** श्रीगोपाल नारसन
**नैनीताल :** शीतल तिवारी
**अल्मोड़ा :** संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
**विकासनगर :** अजय शर्मा
**प्रसार :** रमेश सिंह रावत

**संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)**
**मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164**
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

# भ्रष्टाचार और मंत्री के बेटों की गिरफ्तारी

यह स्थापित तथ्य है कि अधिकतर सरकारी योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पातीं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। इस योजना की शुरूआत इस मकसद से की गई थी कि गरीब परिवारों को साल में कम से कम सौ दिन रोजगार मिल सकेगा और उन्हें अपने भरण-पोषण के लिए किसी दूसरी योजना का मुखापेक्षी नहीं रहना पड़ेगा। मगर शुरूआती वर्षों में ही इसमें भ्रष्टाचार उजागर होने लगे थे। फर्जी नाम दर्ज कर काम देने की बड़ी चालबाजियां सामने आई थीं। उसे रोकने के कई उपाय किए गए, पर इस पर पूरी तरह विराम नहीं लग सका। इस योजना को बंद करने या इसका स्वरूप बदलने का फैसला इसलिए नहीं किया जा सका कि संविधान में इसकी गारंटी दी गई है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का ताना-बाना संबंधित महकमों में ही बुना जाता है। इसका ताजा उदाहरण गुजरात में मनरेगा के तहत फर्जी तरीके से कार्य निष्पादन के दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की रकम भुना लेने का है। पुलिस ने इस मामले में अब तक ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सड़क, बांध, पुलिया आदि निर्माण के लिए सामग्री मुहैया कराने का ठेका दिया गया था। घोटाले ने इसलिए तूल पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया है कि इसमें वहां के पंचायत और कृषि राज्यमंत्री के दो बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी एजंसियां भी मनरेगा परियोजनाओं में शामिल थीं। उन्होंने कार्यों का निष्पादन किए बगैर फर्जी दस्तावेज जमा कर भुगतान प्राप्त कर लिया। मनरेगा की जिन परियोजनाओं में उन्होंने घोटाला किया, वे वहां के आदिवासी इलाकों में चलाई जा रही थीं। इसके अलावा, फिलहाल जांच में पैंतीस ऐसी एजंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्होंने 2021 से 2024 के बीच सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत करके जाली दस्तावेजों के आधार पर इकहत्तर करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया। अभी तक जिला ग्रामीण विकास एजंसी यानी डीआरडीए की जांच में सामने आए एक जिले के तथ्यों के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरे राज्य में इस योजना के तहत कितने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ होगा। उन आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिनके लिए ये परियोजनाएं चलाई तो गई थीं, पर वे केवल कागजों में दर्ज होकर रह गईं। आमतौर पर गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम जमीन पर कम ही उतर पाते हैं। दिखाने के लिए जो कुछ काम होते भी हैं, उनकी गुणवत्ता सदा संदिग्ध रहती है। उनमें इस्तेमाल सामग्री और कामकाज की गुणवत्ता इस कदर खराब होती है कि सड़कें, पुल-पुलिया वगैरह पहली ही बारिश में धुल कर साफ हो जाते हैं। ग्रामीण विकास के नाम पर अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से, मगर वास्तव में उनसे गांवों का चेहरा कितना बदला है, कहना मुश्किल है। ऐसे वक्त में, जब अस्सी करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त के राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना में इतने बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार विकास के दावों का विद्रूप ही कहा जाएगा। गुजरात को विकास के आदर्श के रूप में प्रचारित किया जाता है। जब वहां स्थिति ऐसी है, तो दूसरे राज्यों में इस योजना की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है।

**कुँवर राज अस्थाना**

# भाजपा सरकार की नीति है, केवल नाम बदलो, हालात मत बदलो: *यशपाल आर्य*

श्री यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एवं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल समेत विभिन्न खेल स्टेडियम का नाम परिवर्तन संकीर्ण राजनीति का प्रतीक है। नामों को बदलने की प्रवृति गवरनेन्स नहीं बल्कि द्वेष व भेदभाव के आधार पर अपनी किलताओं पर पर्दा डालने की अति चिन्तनीय संकीर्ण राजनीति है। श्री आर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार का जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है और आज सिर्फ नाम बदलने को ही प्रदेश का विकास समझ लिया है। भाजपा सरकार को समझना चाहिए नाम बदलने से काम नहीं बदलता। नाम बदलने से विकास की धारा बदल जायेगी? सत्य ये है की नाम बदलो, ध्यान भटकाओ, असली मुद्दों से भाग जाओ!
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को नाम और काम का अंतर सीखना चाहिए। तीन वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है, विकास का काम कब शुरू होगा। जमीन पर कोई ठोस काम नहीं दिखा सकते, केवल भ्रम और प्रचार करते हैं।

श्री आर्य ने कहा कि भाजपा प्रदेश के हालात बदलने वाली सरकार नहीं बल्कि नाम बदलने वाली सरकार चला रही है क्योंकि भाजपा के लिए ये नया नहीं है देश की यूपीए सरकार के समय की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जिसमे प्रधानमंत्री जन धन योजना यूपीए की मूल बचत बैंक जमा खाता थी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम थी। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन थी। यहां तक कि श्री मोदी जी का प्रमुख कार्यक्रम ''मेक इन इंडिया'' भी नए नाम के तहत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहले की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना थी, स्किल इंडिया राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम थी। मिशन इंद्रधनुष सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था और पहले एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण था। भाजपा के पास विभिन्न मुद्दों पर जनता को गुमराह करने के सिवा उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है।

श्री आर्य ने कहा कि सवाल ये है की नाम बदलने से क्या बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? महंगाई कम हो जाएगी? सड़क, बिजली, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाएगी।

## सरकार ने किसी स्टेडियम का नाम नहीं बदला

### अजय अग्रवाल (निदेशक खेल) ने कहा भ्रामक खबरों से रहे सावधान

खेल विभाग द्वारा किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है। केवल सम्पूर्ण खेल परिसर को नाम दिया गया है। जिसमें स्थापित विभिन्न खेल अवस्थापना सुविधाओं के जो नाम पूर्व से प्रचलित है। वे यथावत् रहेगे।

विभाग के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर खेल परिसर, जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद खेल परिसर, जनपद ऊधमसिंह के रूद्रपुर खेल परिसर एवं जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित गोलापार खेल परिसर में निर्मित की गयी अवस्थापना सुविधाओं की पहचान तथा आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के दृष्टिगत प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों एवं आगुन्तकों को आयोजन स्थलों की पहचान को ध्यान में रखते हुये रायपुर खेल परिसर देहरादून का नाम रजत जयंती खेल परिसर, गौलापार खेल परिसर हल्द्वानी का मानसखंड खेल परिसर, रूद्रपुर खेल परिसर ऊधमसिंह नगर का शिवालिक खेल परिसर तथा रोशनाबाद खेल परिसर हरिद्वार का नाम योग स्थली खेल परिसर किया गया है।

इस संबंध में प्रभारी अपर निदेशक खेल अजय कुमार अग्रवाल द्वारा जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि रजत जयंती खेल परिसर के अन्तर्गत निर्मित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर देहरादून, राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी एवं अन्य सभी अवस्थापनाओं तथा मानसखंड खेल परिसर हल्द्वानी के अन्तर्गत निर्मित इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स सोसाइटी, हॉकी ग्राउण्ड, तरणताल, मल्टीपरपज हॉल एवं अन्य सभी अवस्थापना, शिवालिक खेल परिसर ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत निर्मित मनोज सरकार स्टेडियम, मल्टीपरपज हॉल, वेलोड्रम एवं अन्य सभी अवस्थापनाओ के साथ योगस्थली खेल परिसर हरिद्वार के अन्तर्गत निर्मित वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम, मल्टीपरपज हॉल, तरणताल एवं अन्य सभी अवस्थापना सुविधाओं का नाम पूर्ववत रखा गया है। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अपर निदेशक खेल द्वारा जारी विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि उक्त परिसरों में स्थापित स्टेडियमों के पूर्व में किये गये नामकरण को समाप्त करते हुये नये नामकरण किये गये हैं। उन्होंने ऐसी सूचनाओं को भ्रामक एवं तथ्यों से परे बताते हुए स्पष्ट किया है कि पूर्व में नामांकित किये गये किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है। खेल विभाग द्वारा मात्र सम्पूर्ण खेल परिसर को नाम दिया गया है। जिसमें स्थापित विभिन्न खेल अवस्थापना सुविधाओं के जो नाम पूर्व से प्रचलित है। वे यथावत् रहेगे और भविष्य में बनने वाली खेल अवस्थापनायें इसी परिसर में समाहित रहेगी।

# शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का बाजार

(लेखक डॉ. ओंकार सिंह वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड के कुलपति हैं।)

हर साल की तरह, प्रवेश सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सार्वजनिक स्थान, सड़क किनारे आदि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विज्ञापनों से भर जाते हैं। एक सटीक प्रवेश सूचना जारी करने से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर बड़े-बड़े लुभावने विज्ञापन देने तक का यह बदलाव सभी स्तरों के शैक्षणिक संस्थानों यानी प्राथमिक, माधयमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में एक आम बात हो गई है। फिर भी, लक्षित दर्शकों की अलग-अलग अपेक्षाओं के कारण विभिन्न स्तरों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली अलग-अलग होती है। हालाँकि, विज्ञापनों के पीछे मुख्य उद्देश्य छात्रों को प्रवेश के लिए आकर्षित करना है। शायद, स्व-वित्तपोषित निजी संस्थानों की संख्या में वृद्धि और उनके संचालन और विकास के लिए प्रवेश राजस्व को अधिकतम करने की अंतर्निहित चुनौतियां, अन्य मजबूर करने वाली परिस्थितियों के साथ-साथ स्पष्ट कारण हैं, जिन्होंने प्रवेश के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। प्रवेश विज्ञापन एक नया मानदंड बन गया है, इसलिए इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रचार सामग्री में रचनात्मक और प्रभावशाली ऑडियो-वीडियो या लिखित सामग्री- प्रिंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आउटडोर विज्ञापन और अन्य माधयमों में उपयोग की जाने वाली सामग्री पर्याप्त बौद्धिक और वित्तीय निवेश को दर्शाती है। निस्संदेह, आकर्षक सामग्री वाले ऐसे विज्ञापन ध्यान आकर्षित करते हैं और छात्रों और समाज में सामान्य रूप से रुचि जगाते हैं। लेकिन जुड़ाव का स्तर, संस्थान के बारे में स्मृति प्रतिधारण, भावनात्मक जुड़ाव, संस्थान को याद रखना आदि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड पर निर्भर करता है और जेनरेशन Z और मिलेनियल्स के लिए भी अलग-अलग होता है।

उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा विज्ञापन के विवरण में गहराई से जाने पर महसूस होता है कि इनमें सामान्य प्रदर्शन उनकी उपलब्धियों के बारे में होता है, जैसे कि छात्र प्लेसमेंट, प्लेसमेंट वेतन पैकेज, मान्यताएँ, रैंकिंग, आईपीआर, (IPRs) देश और विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता (MoUS) ज्ञापन, उद्योग संबंधा, बुनियादी ढाँचा, सुविधाएँ, संस्थागत मान्यताएँ, कार्यक्रम की विशिष्टताएँ और छात्रों व अभिभावकों में प्रभाव पैदा करने के लिए प्रदर्शित करने योग्य अन्य चीजें। कई परिस्थितियों में, दिखाए गए विवरण एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन्न होते हैं और सभी प्रयास चुपचाप दूसरों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो प्रचार विशेषताओं, विशेष रूप से रैंकिंग, मीडिया रिपोर्ट, सहयोग और प्लेसमेंट से जुड़े कतिपय पहलुओं को उजागर करते हैं।

**रैंकिंग:** संस्थागत रैंकिंग को देखने से यह स्पष्ट होता है कि आज बड़ी संख्या में रैंकिंग ढाँचे उपलब्धा हैं जो परस्पर रैंक प्रदान करते हैं कतिपय परिस्थितियों में संस्थान जो संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान की सार्वजनिक धारणा के साथ सुसंगत नहीं होती हैं। इसके अलावा, सभी रैंकिंग ढाँचों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता एक जैसी भी नहीं होती है, लेकिन विज्ञापनों में पेश की गई रैंक संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान के बारे में पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण बना सकती है और इस प्रकार से बनी धारणा से हितधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मीडिया रिपोट: उच्च शिक्षा संस्थान की मीडिया रिपोर्ट उनके बारे में धारणा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए, कभी-कभी उच्च शिक्षा संस्थान कुछ ऐसी सामग्री को भी आगे बढ़ाते हैं जो विज्ञापन के रूप में प्रकाशित होती है परन्तु समाचार आइटम की तरह दिखती है। ऐसी स्थिति में जहाँ अधिकांश लक्षित दर्शक समाचार आइटम और विज्ञापन के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं होते हैं, विज्ञापन के आधाार पर भ्रामक राय बना लेते हैं। यह देखते हुए कि प्रिंट मीडिया में समाचार आइटम अधिाक विश्वसनीय होते हैं, भुगतान कर छपवाये गए विज्ञापन या भ्रामक प्रस्तुतियों की ऐसी कोई भी पहल उम्मीदवारों को संबधित उच्च शिक्षा संस्थान की वास्तविक स्थिति से अवगत होने से वंचित कर सकती है।

सहयोग: शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के सामूहिक गुणात्मक विकास के एक हिस्से के रूप में देश के भीतर या देशों में उद्योगों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों या उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच आपसी सहयोग की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आम तौर पर अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों या उद्योगों/संगठनों के साथ ये सहभागिताएँ संयुक्त अनुसंधान, डिग्री कार्यक्रम, इंटर्नशिप, परियोजनाएँ या अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण चलाने के लिए होती हैं। कुछ मामलों में, कतिपय उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा इन सहयोगों का उल्लेख करते हुए प्रभावशाली तरह से तैयार की गई टैगलाइन गलत धारणाएँ पैदा करती हैं। बहुत संभव है कि जिस तरह से सहयोग का इस तरह से पूंजीकरण किया जाता है, और उसे भ्रामक तरीके से सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत किया जाता है, वह संबंधित सहयोगी के ज्ञान में भी नहीं हो और सहयागी संस्था द्वारा उनके ब्रांड का लाभ उठाने के कारण उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

**प्लेसमेंट:** कई स्थितियों में, उच्च शिक्षा संस्थान चुनिंदा प्लेसमेंट आँकड़े भी प्रकाशित करते हैं, जिनमें प्लेसमेंट की संख्या, प्लेसमेंट के प्रकार, संभावित नियोक्ताओं के नाम, वेतन पैकेज आदि शामिल होते हैं। अच्छे पैकेज दिखाने वाले ये आँकड़े प्रवेश चाहने वालों के मूड और योजनाओं को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। गौर तलब है कि प्लेसमेंट संस्था के छात्रों की क्षमता और संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा समय पर नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाने पर निर्भर करता है और इसे हर छात्र का विशेषाधिकार नहीं माना जा सकता है। कुछ प्लेसमेंट के भारी पैकेज के साथ दिखावा करने के भी मामले सामने आए हैं जो लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, फिर भी भ्रामक प्रचार जारी रहता है।

# उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तस्वीर साफ

**उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पिछले डेढ़ साल से अटके हुए हैं। अब पूरी संभावना है कि हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में जुलाई माह तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। पिछले दिनों धामी सरकार की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया। जिसमें बताया गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार तैयार है। सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि ओबीसी आरक्षण की सिफारिशें लंबित होने के कारण चुनाव में देरी हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। निर्वाचक नामावलियों में नाम खोजने की सुविधा के लिए मतदाता सूची पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गयी है। आयोग इन दिनों ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। आयोग जुलाई में अधिसूचना जारी करेगा।**

उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तस्वीर साफ हो गई है। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों के गांवों की सरकार दो माह के अंदर बनने जा रही है। इसके लिए प्रदेश की धामी सरकार भी तैयार है। पिछले डेढ़ साल से प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कई पेज फंसे हुए थे। ओबीसी आरक्षण सूची का मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा। अब पूरी संभावना है कि जुलाई महीने में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो जाएंगे। पिछले दिनों धामी सरकार की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया। जिसमें बताया गया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार तैयार है। सरकार ने हाईकोर्ट में शपथपत्र के जरिए ये जानकारी दी है। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने पंचायत चुनाव संबंधी शपथपत्र दाखिल करने की पुष्टि की है। जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष व ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाने को चुनौती देती कई याचिकाएं हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि उनकी पूरी तैयारी है। सरकार के स्तर से आरक्षण के संबंध में निर्णय होना है। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई में अधिसूचना जारी करेगा। सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि ओबीसी आरक्षण की सिफारिशें लंबित होने के कारण चुनाव में देरी हुई। याचिकाकर्ताओं ने प्रशासक नियुक्ति का विरोध किया है पर सरकार का कहना है कि इससे पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है। जिसके आधार पर राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो गयी है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। निर्वाचन आयोग इन

दिनों ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का दो दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। लेकिन चुनाव न हो पाने की स्थिति में शासन की ओर से पंचायतों में अगले 6 महीने में लिए प्रशासक बिठा दिए गए। 27 मई को ग्राम पंचायतों, 29 मई को क्षेत्र पंचायतों और 31 मई को जिला पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में शासन स्तर पर प्रशासकों के कार्यकाल को अगले 6 महीने तक बढ़ाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधित पत्र तैयार होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा। जहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। भले ही उत्तराखंड शासन प्रशासकों का कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने को लेकर कसरत शुरू कर दी हो, लेकिन राज्य सरकार 15 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की दिशा में भी काम कर रही है। इसी क्रम में प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2025 और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव के मद्देनजर शासन, पदों का आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।

**12 जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट जारी की:** उत्तराखंड में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। गुरुवार शाम को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए पंचायत निर्वाचक नामावलियों में नाम खोजने की सुविधा हेतु मतदाता सूची पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गयी है। पंचायतों के मतदाता अपना नाम आयोग के उक्त पोर्टल पर ''पंचायत मतदाता खोजें'' पर क्लिक कर खोज सकते हैं। इस संबंध में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राहुल कुमार गोयल द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि घर-घर जाकर कराये गये विस्तृत पुनरीक्षण के अनुसार दिनांक 17.01.2025 को अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के नाम खोजे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम कतिपय कारणों से निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन में सम्मिलित होने से रह गये थे उन मतदाताओं के नाम आयोग द्वारा दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 22.03.2025 तक प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में (हरिद्वार जनपद को छोड़कर) ग्रामवार बैठक बुलाकर निर्वाचक नामावली प्रकाशित करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया था। उसके बाद भी ग्राम पंचायत के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने हेतु उपलब्ध कराये गये आवेदनों पर जनपदों द्वारा आयोग से स्वीकृति प्राप्ति के बाद उक्त पोर्टल पर खोजे जा सकेंगे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनपदों के माध्यम से प्रयास किए गए हैं कि किसी भी पात्र निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से ना छूटे तथापि अभी भी पात्र मतदाता अपने निकटतम विकास खण्ड अथवा तहसील कार्यालय में प्रपत्र भरकर नाम जोड़ने/संशोधन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12 जिलों में पंचायतों के संभावित पदों की संख्या इस प्रकार है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पदों की संख्या 7499 है। सदस्य ग्राम पंचायत 55589, प्रधान ग्राम पंचायत 7499, उप ग्राम पंचायत 7499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2974, सदस्य जिला पंचायत 358, प्रमुख क्षेत्र पंचायत 89, ज्येष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत 89, कनिष्क उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत 89, जिला पंचायत अध्यक्ष 12 और उप जिला पंचायत अध्यक्षों की संख्या 12 है।

## 'एक देश-एक चुनाव' पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने उत्तराखंड से लिया फीडबैक

एक देश-एक चुनाव पर केंद्र सरकार द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति ने सभी राज्यों से छह माह में एक साथ चुनाव के का-नुकसान पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। यह संयुक्त संसदीय समिति उत्तराखंड में दो दिनों से हितधारकों और राजनीतिक दलों से सुझाव लिया। इस दौरान सभी दलों ने समिति को अपने-अपने सुझाव दिए हैं। 21 मई को संसदीय समिति का 41 सदस्य प्रतिनिधिमंडल देहरादून पहुंच था। इसमें 39 सांसद और दो मनोनीत सदस्य शामिल थे। समिति ने दो दिनों तक लगातार एक देश एक चुनाव पर सभी से फीडबैक लिया। इस दौरान राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे छह महीने के भीतर विभागवार रिपोर्ट समिति को सौंप देंगे। एक देश, एक चुनाव' पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पी पी चौधरी ने गुरुवार को कहा कि सभी राज्यों से एक साथ चुनाव होने के नफा-नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है जिससे समिति को अपनी रिपोर्ट बेहतर बनाने में सहयोग मिले। उत्तराखंड में अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत में चौधरी ने कहा कि राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे छह महीने के भीतर यह रिपोर्ट समिति को सौंप दें। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा देश हित का है, इसलिए आने वाले दिनों में जो भी फैसला किया जाएगा, उसमें देश हित ही सर्वोपरि रहेगा। चौधरी ने बताया कि समिति ने अभी तक महाराष्ट्र और उत्तराखंड से 'एक देश एक चुनाव' पर जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि समिति सभी राज्यों से संपर्क करेगी। उन्होंने कहा कि समिति अपने स्तर से तो प्रतिक्रिया ले ही रही है लेकिन सभी राज्यों से एक साथ चुनाव के प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ-हानि पर विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है ताकि समिति को अपनी रिपोर्ट और बेहतर बनाने में सहयोग मिल पाए। जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करने के मामले में समिति के सामने कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है और न ही वह किसी भी तरह की जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि यह काम देश हित से जुड़ा अत्यंत महत्व का है इसलिए जोर ठोस काम करने पर है। चौधरी ने कहा कि यदि एक साथ चुनाव होने शुरू हो गए तो देश की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ रुपये का लाभ पहुंचेगा जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.6 फीसदी होगा। उन्होंने कहा कि मौसम भी चुनाव को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पिछले कई वर्षों से लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव के संबंध में बहुत सी बातें बाद में निर्धारित होनी है लेकिन अप्रैल-मई में एक साथ चुनाव कराने के सुझाव को उपयुक्त माना जा रहा है।

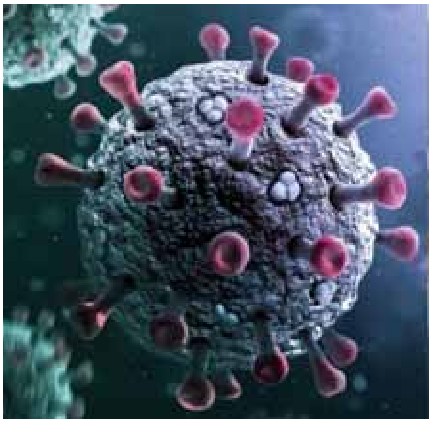

# देश में फिर लौटा कोरोना, अलर्ट मोड पर धामी सरकार

**देश में एक बार फिर कोरोना की दस्तक हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 का नया वेरिएंट एक बार फिर पैर पसारने लगा है। भारत में मौजूदा समय में 312 एक्टिव कोरोना केस सामने आए हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की तो धामी सरकार कोरोना के नए वेरिएंट जेएन.1 को लेकर नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट के दो नए केस सामने आए हैं। हालांकि दोनों बाहरी राज्यों के हैं। एक मरीज बेंगलुरु और दूसरा गुजरात का है। दोनों को उपचार के लिए ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने अधिकारियों को स्क्रीनिंग जांच और अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने और लक्षणों पर ध्यान देने की अपील की गई है। खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों को बाहर जाने से बचने और टेस्ट कराने की सलाह दी गई। साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सिफारिश की गई।**

देश में एक बार फिर कोरोना लौट आया है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों में कोविड-19 का नया वेरिएंट एक बार फिर पैर पसारने लगा है। भारत में मौजूदा समय में 312 एक्टिव कोरोना केस सामने आए हैं। इसमें दिल्ली से 23, हरियाणा से 5, गुजरात से 33, महाराष्ट्र से 56 केस सामने आए हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट मोड पर आ गई हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की तो धामी सरकार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट के दो नए केस सामने आए हैं। हालांकि दोनों बाहरी राज्यों के हैं। एक मरीज बेंगलुरु और दूसरा गुजरात का है। दोनों को उपचार के लिए ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने बताया कि गुजरात से आई 57 साल की एक महिला ऋषिकेश में पूजा के लिए आई थी, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए थे। जब उन्होंने जांच कराई तो उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। इसके बेंगलुरु से एक डॉक्टर उत्तराखंड आए हैं, उनमें भी कोरोना की पुष्टि हुई है। जिनका इलाज घर पर ही चल रहा है। सुनीता टम्टा ने बताया कि उत्तराखंड में कोई ऐसा एक्टिव कैसे नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में सैंपलिंग को बढ़ाया जाए। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि यह वायरस मौजूदा इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है और इंसानों से इंसानों

## स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए जारी किए निर्देश

कोविड की आशंका को लेकर उत्तराखंड में प्रशासन अलर्ट पर है। अब अस्पतालों में बेड रिजर्व किए जाएंगे। सरकार और निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पैथोलॉजी लैब को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इनफ्लुएंजा, सार्स से पीड़ित हर मरीज के अनिवार्य रूप से कोविड जांच कराई जाएगी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य महानिदेशालय के साथ ही सभी जिलों और मेडिकल कॉलेजों के अफसरों के साथ बैठक की। जिसके बाद अब स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से अस्पतालों के लिए एडवायजरी जारी की गई है। जिसमें अस्पतालों में लक्षण वाले मरीजों की जांच के साथ ही पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेसिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कोविड मरीजों के बारे में तत्काल सूचना देने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों को हर दृष्टि से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना नए वेरिएंट के लक्षण इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों से मिलते-जुलते हैं और यह जानलेवा भी है। उत्तराखंड में कोविड-19 की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएमओ डा. मनोज कुमार शर्मा ने जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और पैथोलाजी लैबों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ ने कहा कि इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों (आइएलआइ) और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (सार्स) से पीड़ित हर मरीज की अनिवार्य रूप से कोविड जांच कराई जाए। जांच की जानकारी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफार्मेशन प्लेटफॉर्म (आइएचआइपी) पर दर्ज की जाए। उन्होंने सभी अस्पतालों को आइसोलेशन वार्ड चिह्नित करने, फ्लू क्लीनिक संचालित करने और संदिग्ध मरीजों को समय रहते आइसोलेट करके उनका उपचार शुरू करने के निर्देश भी दिए।

में तेजी से फैल सकता है। भले ही देशभर में फिलहाल कोरोना वायरस केस की संख्या पिछली वेव के मुकाबले कम हैं, लेकिन मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों में वायरस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को स्क्रीनिंग जांच और अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से सतर्क रहने और लक्षणों पर ध्यान देने की अपील की गई है।

एशिया के कुछ देशों में कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जेएन.1, जो बहुत जल्दी फैलता है और अब इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। हालांकि राहत की बात ये है कि मरीजों में ज्यादा लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों को बाहर जाने से बचने और टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। साथ ही, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सिफारिश की गई है।

# राज्य विश्वविद्यालयों के संबद्धता संबंधी अव्यवहारिक फरमान से अधिकांश कॉलेज बंदी के कगार पर: डॉ. सुनील अग्रवाल

निजी कॉलेज एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉ. सुनील अग्रवाल ने कॉलेजों की संबद्धता विस्तारण संबंधित राज्य विश्वविद्यालयों के अव्यवहारिक फरमान पर आपत्ति उठाई है एक विस्तृत बयान जारी कर डॉ. सुनील अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध निजी कॉलेजों में जब कोई कोर्स शुरू किया जाता है तो उसके लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक वर्ष के संबद्धता शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक कोर्स हेतु एक प्राभुत राशि की फिक्स्ड डिपॉजिट की मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा करने का प्रावधान है जो ट्रेडिशनल कोर्सों हेतु रुपए 2 लाख एवं व्यावसायिक कोर्सों हेतु रुपए 4 लाख निर्धारित थे विगत 14 दिसंबर 2016 के एक शासनादेश संख्या 649 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2009 का हवाला देते हुए उक्त प्राभुत राशि को अ व्यावहारिक रूप से बढ़ाकर सामान्य कोर्स हेतु 15 लाख एवं व्यावसायिक कोर्स हेतु 35 लाख निर्धारित कर दिया गया उस समय पर कॉलेजों द्वारा आपत्ति उठाई जाने पर शासन द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया था लेकिन कमेटी की एक बैठक के बाद उसकी फिर कोई बैठक नहीं हो पाई इस बीच में कॉलेजों में नए कोर्स भी खुलते रहे और स्टूडेंट के एग्जाम्स भी होते रहे कई कॉलेजों में विश्वविद्यालय से संबद्धता विस्तारण तीन-चार साल से नहीं हो पाया था लेकिन छात्रों की परीक्षाएं होती रही संबद्धता विस्तारण न होने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति की समस्या पैदा हुई अब वर्तमान में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को 1 अप्रैल 2024 को पत्र जारी किया गया कि कॉलेजों की पिछले वर्षों की संबद्धता के प्रकरण तुरंत अनुमोदन के करके राज भवन भेजे जाएं और 2025- 26 से संबद्धता हेतु नए नियमों का पालन करवाया जाए राज भवन के उक्त पत्र के आलोक में राज्य विश्वविद्यालयों ने सभी कक्कलेजों का भौतिक निरीक्षण कर लिया है लेकिन उसके बावजूद 2024 तक की संवाददाता विस्तारण के पत्र भी अभी तक कॉलेजों को नहीं भेजे गए हैं और अब वर्तमान 2025 -26 के सत्र हेतु सभी कॉलेजों को प्राभुत राशि रुपए 15 लाख और रुपए 35 लाख जमा करने के आदेश जारी कर दिए हैं यहां यह उल्लेखनीय है कि हमारे उत्तराखंड के पैरेंटल स्टेट उत्तर प्रदेश में सन 2002 से जो प्राभुत राशि निर्धारित की गई थी वह अभी तक यथावत है जो विभिन्न कोर्सों हेतु रुपए 2 लाख से रुपए 6 लाख तक निश्चित है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है यहां यह भी उल्लेखनीय है की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2009 में जहां प्राभुत राशि का प्रावधान किया गया है वहां स्पष्ट उल्लेख है कि इसका निर्धारण संबद्धता देने वाली अथॉरिटी द्वारा भी किया जा सकता है यानी यह प्राभुत राशि बाध्यकारी नहीं है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोविड के समय जब कॉलेज के समक्ष स्टाफ को सैलरी देने की समस्या हुई तो विश्वविद्यालय से स्टाफ को सैलरी देने हेतु उक्त प्राभुत राशि के इस्तेमाल हेतु अनुरोध किया गया लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली जिससे साफ है कि इस प्राभुत राशि का कॉलेज संकट काल में भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते डॉ अग्रवाल ने कहा कि मेरी जानकारी में यह भी आया है के अभी तक किसी अन्य प्रदेश ने प्राभुत राशि को इस तरह से अव्यवहारिक रूप से नहीं बढ़ाया है लेकिन हमारी प्रदेश सरकार में तो किसी भी नीति को बिना उसके गुण दोष समझे सबसे पहले लागू करने की जैसे होड़ सी लगी रहती है डॉ. अग्रवाल ने कहा की वैसे ही छोटे से उत्तराखंड में निजी विश्वविद्यालयों की भरमार राज्य सरकार द्वारा कर दिए जाने से कॉलेजों में छात्रों का अभाव हो चुका है और ऐसे में राज्य विश्वविद्यालयों के इस फरमान से कॉलेजों के सामने अपने कोर्सों को बंद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। इस संबंध में निजी कॉलेज एसोसिएशन की पिछले दिनों वर्तमान उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रणजीत सिंहा जी से सकारात्मक वार्ता हुई है लेकिन विश्वविद्यालयों के ताजा फरमान से अधिकांश कॉलेज अपने कोर्स सरेंडर करने का मन बना चुके हैं।

# उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा 'ऑपरेशन सिंदूर'

**प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर एक पूरा अध्याय शुरू करने का निर्णय लिया है। पूरे उत्तराखंड में 451 पंजीकृत मदरसों में 50,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं, जो अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अध्ययन करेंगे। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने यहां जारी एक बयान में कहा, ''हम मदरसों में सफल ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को शामिल करेंगे ताकि हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को यह मालूम हो सके कि यह ऑपरेशन क्या था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी।**

उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार, 20 मई को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। पिछले दिनों सात मई को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करके कई आतंकी अड्डों को तहस-नहस कर दिया था। अब उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर एक पूरा अध्याय शुरू करने का निर्णय लिया है। जिसमें भारतीय सेना की वीरता और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक कहानी शामिल होंगी। पूरे उत्तराखंड में 451 पंजीकृत मदरसों में 50,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं, जो अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि उत्तराखंड के मदरसों के पाठ्यक्रम में, हाल में भारतीय सैन्य बलों द्वारा पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की गाथा को शामिल किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने यहां जारी एक बयान में कहा, ''हम मदरसों में सफल ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को शामिल करेंगे ताकि हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को यह मालूम हो सके कि यह ऑपरेशन क्या था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी।'' पाकिस्तान को 'नापाक मुल्क' बताते हुए कासमी ने कहा कि जिस तरह से उसने हमारे देश पर हमला किया और पहलगाम में 'हमारे निहत्थे भाइयों' का कत्ल किया, उसके लिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। उन्होंने इस कृत्य को कुरान की भी अवहेलना बताया। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्णय पर अमल के लिए जल्दी ही पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलायी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में लगातार मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्रदेश के मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है और मदरसों को आधुनिक बनाया जा रहा है।

## पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर से लिया बदला

22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने सात मई को आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक किया है। इस कार्रवाई का नाम 'ऑपरेशन सिंदूर' रखा गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुझाया गया है। पहलगाम में हुए हमले में आतंकवादियों ने पुरुषों को निशाना बनाया था, जिसमें कई महिलाएं विधवा हो गई हैं। इसलिए भारत की तरफ से की गई कार्रवाई को 'ऑपरेश सिंदूर' नाम दिया गया है। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि अब आतंकियों की बची-कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी। मैं आज बिहार की धरती से पूरी दुनिया से कहता हूं कि भारत हर आतंकी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, उन्हें खोजेगा और उन्हें सजा देगा। हम उन्हें धरती के किसी भी कोने तक खदेड़ेंगे।

# बॉलीवुड अभिनेता मुकुल देव का 54 साल की आयु में निधन

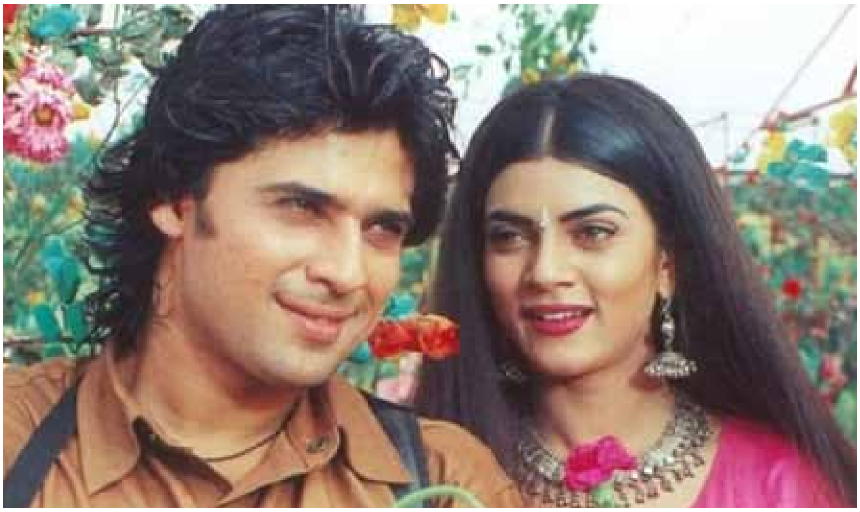

**मुकुल देव एक ऐसे अभिनेता थे, जिन्होंने पायलट की नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई और रातोंरात स्टार बन गए। मुकुल देव ने 1996 में अपनी पहली फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें उनकी जोड़ी सुष्मिता सेन के साथ थी। इस फिल्म का गाना 'जादू भरी आंखों वाली सुनो' उस दौर में खूब पसंद किया गया, और मुकुल की स्मार्ट पर्सनैलिटी ने उन्हें तुरंत फैंस का चहेता बना दिया। वह हिम्मतवाला, यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार, जय हो, भाग जॉनी जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वे कुछ समय से बीमार थे और हाल ही में आईसीयू में भर्ती किए गए थे। उनकी मौत का कारण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अचानक मुकुल देव के निधन से बॉलीवुड के कई कलाकारों ने शोक जताया।**

90 के दशक में बॉलीवुड में कई हिट फिल्म देने वाले अभिनेता मुकुल देव का 54 साल की आई मुंबई में निधन हो गया है। मुकुल देव एक ऐसे अभिनेता थे, जिन्होंने पायलट की नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई थी और रातोंरात स्टार बन गए। जानकारी के मुताबिक मुकुल देव का शुक्रवार रात निधन हुआ। शनिवार को उनके दोस्तों को जब उनके निधन की खबर मिली तो वे उनके घर पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक, वे कुछ समय से बीमार थे और हाल ही में आईसीयू में भर्ती किए गए थे। उनकी मौत का कारण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अचानक अभिनेता मुकुल देव के निधन से बॉलीवुड के कई कलाकारों ने शोक जताया है। विंदु दारा सिंह, जो 'सन ऑफ सरदार' में मुकुल के साथ काम कर चुके हैं, ने भी इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने शोक जताते हुए कहा कि अब मुकुल खुद को कभी बड़े पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री ने एक प्रतिभाशाली कलाकार को खो दिया है। विंदू दारा सिंह ने कहा, 'अपने माता-पिता की मौत के बाद मुकुल खुद को अलग-थलग कर लिया था। वह घर से बाहर भी नहीं निकलता था और किसी से भी नहीं मिलता था। पिछले कुछ दिनों में उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वह अस्पताल में था। उसके भाई और उसे जानने और प्यार करने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वह एक अद्भुत व्यक्ति था, और हम सभी उसे याद करेंगे। मुकुल की दोस्त और एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल ने भी इंस्टाग्राम पर दिवंगत एक्टर के साथ एक फोटो पोस्ट की। इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुकुल ने कभी किसी से अपनी हेल्थ के बारे में बात नहीं की। उनका व्हाट्सएप पर एक दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें वे अक्सर बात करते थे। उन्होंने इमोशनल होकर कहा, 'मैं सुबह इस खबर के साथ उठी। मैं तब से उनके नंबर पर कॉल कर रही हूं, उम्मीद है कि वे फोन उठाएंगे'।

**दिल्ली में जन्मे मुकुल ने साल 1996 में दस्तक फिल्म से किया था डेब्यू**

मुकुल देव ने 1996 में अपनी पहली फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें उनकी जोड़ी सुष्मिता सेन के साथ थी। इस फिल्म का गाना 'जादू भरी आंखों वाली सुनो' उस दौर में खूब पसंद किया गया, और मुकुल की स्मार्ट पर्सनैलिटी ने उन्हें तुरंत फैंस का चहेता बना दिया। वह हिम्मतवाला, यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार, जय हो, भाग जॉनी जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने ना सिर्फ हिंदी बल्कि पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इस शानदार डेब्यू के बाद उनकी राह आसान नहीं थी। मुकुल का जन्म 17 सितंबर 1970 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरि देव दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, और उनके बड़े भाई राहुल देव भी एक मशहूर अभिनेता हैं। मुकुल ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से पायलट की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन एक्टिंग के जुनून ने उन्हें मुंबई खींच लिया। दस्तक से पहले वह टीवी शो मुमकिन में नजर आए थे। उनकी प्रतिभा को देखकर अमिताभ बच्चन की कंपनी ने उन्हें फिल्म नाम क्या है के लिए साइन किया, लेकिन वह फिल्म नहीं बनी। इसके प्रोमो देखकर महेश भट्ट ने उन्हें दस्तक में मौका दिया था। फिल्म दस्तक में मुकुल ने एसीपी रोहित मल्होत्रा का किरदार निभाया था, और सुष्मिता के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीता था। हालांकि, इसके बाद उनकी फिल्में जैसे किला, वजूद, और मुझे मेरी बीवी से बचाओ बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। सुष्मिता की तरह उनका करियर लीड रोल में चमक नहीं पाया, लेकिन उन्होंने यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार, और जय हो जैसी फिल्मों में सहायक किरदारों से खूब वाहवाही बटोरी। उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें यमला पगला दीवाना के लिए 7वां अमरीश पुरी अवॉर्ड भी मिला था।

# क्यों जनता भ्रष्टाचार का अनचाहा भार ढ़ोये?

**ललित गर्ग**

विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न प्रांतों की सरकारों, विभिन्न गरीब कल्याण की योजनाओं, न्यायिक क्षेत्र एवं उच्च जांच एजेंसियों में भ्रष्टाचार की बढ़ती स्थितियां गंभीर चिन्ता का विषय है। ऐसा लगता है आज हम जीवन नहीं, राजनीतिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक मजबूरियां जी रहे हैं। ऐसा भी लगता है न्याय, राजनीति एवं प्रशासन की सार्थकता एवं साफ-सुथरा उद्देश्य नहीं रहा, स्वार्थपूर्ति का जरिया बन गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा एक असामान्य घटनाक्रम के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के तीन अधिकारियों को उसी सीबीआई की हिरासत में भेज देना न केवल चिन्ताजनक एवं शर्मनाक है बल्कि विडम्बनापूर्ण है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का बुगल बजाय हुए है, जिससे राजनीति में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का नया सूरज उदित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सीबीआई जैसी जांच एजेन्सी में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना इस सूरज को उदित होने से पहले ही अंधेरा की ओट में ले रहा है। इससे भी बड़ी त्रासद एवं निराशाजनक है गुजरात में 71 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाले में मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के दो बेटों का गिरफ्तार होना। राजनीति एवं कार्यपालिका के साथ न्याय पालिका के क्षेत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में कथित तौर पर नकदी मिलना भ्रष्टाचार के सर्वत्र व्याप्त होने को दर्शा रहा है। जनता कब तक भ्रष्टाचार का अनचाहा भार ढ़ोती रहेगी। कैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भ्रष्टाचारमुक्त आदर्श राष्ट्र-निर्माण के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे? कैसे आजादी के अमृत काल में ईमानदार राष्ट्र बना पायेंगे?

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 25 अप्रैल को सीबीआई के तीन अधिकारियों के भ्रष्टता पर अपने आदेश में कहा कि यह सीबीआई, ईडी और ऐसे अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अनूठा मामला है, जिसने हमारी कार्यपालिका और जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया है। इन एजेंसियों का प्राथमिक कर्तव्य अपराध की जांच करना और भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा दिलाना है। लेकिन इन उच्च जांच एजेन्सियों के आला अधिकारी ही भ्रष्ट हो तो दूसरों के भ्रष्टाचार मामलों में निष्पक्ष एवं तीक्ष्ण जांच की उम्मीद कैसे संभव है? सीबीआई-भ्रष्टाचार एकमात्र मामला नहीं है, बल्कि यह विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच एक 'बड़ी साजिश' को दर्शाता है, जो अनुचित लाभ या प्रभाव डालने समेत इन विभागों के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए रिश्वत के मामले को दर्शाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के जज भी ऐसे मामलों में लिप्त हो तो समस्या की गंभीरता को सहज ही समझा जा सकता है। निश्चित ही भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जस्टिस वर्मा केस एक दुर्लभ एवं संवेदनशील मौका है। अब इसकी वजह से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस न पहुंचे और जनता का भरोसा बना रहे, इसके लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मामले से जुड़ी जानकारियों को देश से साझा किया। साथ ही, उनकी पहल पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर किया गया और जांच कमिटी बनाकर उसकी रिपोर्ट सरकार व राष्ट्रपति के पास भेजकर महाभियोग की सिफारिश कर दी गई है। यहां से अब गेंद सरकार और संसद के पाले में है। महाभियोग ही एकमात्र तरीका है, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट

के मौजूदा जजों को हटाया जा सकता है। लेकिन, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग चला था, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया यानी वहां भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अब अगर जस्टिस वर्मा का यह मामला महाभियोग तक पहुंचता है, तो वहां भी एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए प्रक्रिया की जटिलता को कम किया जा सकता है? ताकि जजों के भ्रष्टाचार की उचित सजा उनको मिल सके, ऐसी प्रक्रिया से ही न्यायपालिका बिना किसी डर, दबाव या लालच के अपना कर्तव्य भी निभा सके।

भ्रष्टाचार की परतें अपराधियों एवं भ्रष्ट लोगों को बचाने तक ही सीमित नहीं है, अब तो यह गरीबों का निवाला भी छीन रही है। सरकार गरीबों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन बड़ा स्थापित तथ्य है कि अधिकतर सरकारी योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पातीं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। इस योजना की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि गरीब परिवारों को साल में कम से कम सौ दिन रोजगार मिल सकेगा और वे अपना भरण-पोषण कर सकेंगे मगर शुरुआती वर्षों में ही इसमें भ्रष्टाचार उजागर होने लगे थे। फर्जी नाम दर्ज कर काम देने की बड़ी चालबाजियां सामने आई थीं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का ताना-बाना संबंधित महकमों में ही बुना जाता है। इसी का त्रासद उदाहरण गुजरात में मनरेगा के तहत फर्जी तरीके से कार्य निष्पादन के दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की रकम भुना लेने का है। पुलिस ने इस मामले में अब तक ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सड़क, बांध, पुलिया आदि निर्माण के लिए सामग्री मुहैया कराने का ठेका दिया गया था। इस घोटाले ने इसलिए तूल पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया है कि इसमें वहां के पंचायत और कृषि राज्यमंत्री के दो बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है।

गुजरात ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी मनरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के किस्से उजागर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी मनरेगा भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। जिले के कई ब्लॉक में मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। फर्जी हाजिरी और फोटो घोटाले से हर दिन लाखों रुपये की लूट हो रही है। एक ही फोटो को बार-बार इस्तेमाल करके लाखों रुपये निकाले जा रहे हैं। गुजरात में मंत्री के बेटों के द्वारा मनरेगा लूट एवं भ्रष्टाचार अधिक परेशान करने वाला एवं चिन्ता में डालने वाला है। नेता, मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी अच्छे-बुरे, उपयोगी-अनुपयोगी का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मार्गदर्शक यानि नेता शब्द कितना पवित्र व अर्थपूर्ण था पर अब नेता खलनायक बन गया है। नेतृत्व व्यवसायी एवं भ्रष्टाचारी बन गया। आज नेता शब्द एक गाली है। जबकि नेता तो पिता का पर्याय था। उसे पिता का किरदार निभाना चाहिए था। पिता केवल वही नहीं होता जो जन्म का हेतु बनता है अपितु वह भी होता है, जो अनुशासन सिखाता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, विकास की राह दिखाता है। आगे बढ़ने का मार्गदर्शक बनता है।

अब तक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल आदि राजनीतिक दलों में ही भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ रहे थे, अब भाजपा नेताओं एवं मंत्रियों पर भी ऐसे आरोप लगना ज्यादा चिन्ताजनक है। प्रश्न भाजपा का ही नहीं है, भ्रष्टाचार जहां भी हो, उसके खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, नया भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये तत्पर है तो उसकी पार्टी के भीतर भी यदि भ्रष्टाचार है तो उसकी सफाई ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी दल के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का बुगल बजाय हुए हैं तो यह नये भारत, सशक्त भारत, ईमानदार भारत बनाने की सार्थक पहल है। राजनीतिज्ञों, जजों, प्रशासनिक अधिकारियों की साख गिरेगी, तो राष्ट्र की साख बचाना भी आसान नहीं होगा। चहुंओर पसरे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से विकास के दावों का विद्रूप रूप ही सामने आता है। हमारे पास कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनीति ही समाज की बेहतरी का भरोसेमंद रास्ता है और इसकी साख गिराने वाले कारणों में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के बाद तीसरा नंबर कीचड़ उछाल राजनीति का भी है, जिसमें गलत को गलत नहीं माना जाता। ये तीनों ही ऐसे औजार है, जो देश को तबाही की ओर ले जाते हैं। अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का मसला काफी गहरा है और इससे खिलाफ आरपार की लड़ाई के लिए काफी कठोरता, निष्पक्षता, वक्त और ऊर्जा की जरूरत है, सख्त कदम उठाने की अपेक्षा है। ऐसी ही उम्मीदभरी एवं भ्रष्टाचार-निरोधक कार्रवाई से भारत का लोकतंत्र समृद्ध हो सकेगा।

## आईसीएसई बोर्ड रिजल्ट

### सेंट जोसेफ अकेडमी

पार्थ गुप्ता, 99%

वेदांशी पंत, 98.4%

तनिका गुप्ता, 98.2%

ध्रुपद दर्श चौहान, 98.2%

## आईएससी बोर्ड रिजल्ट

### सेंट जोसेफ अकेडमी

शौर्य अग्रवाल
99.25%, विज्ञान

आरव गेरा, 99.25%
विज्ञान

अर्णव पांडे, 99%
विज्ञान

वत्सल खंतवाल,
99%, विज्ञान

श्रेयश यादव,
98.5%, विज्ञान

पंखुड़ी भंडारी, 98%
ह्यूमैनिटीज़

ऋषिता भंडारी,
97.5%, ह्यूमैनिटीज़

अन्या देवरानी
97.5%, ह्यूमैनिटीज़

अनिंदिता प्रभुमेहर सिंह,
96.5%, ह्यूमैनिटीज़

लावण्या दास
98.5%, कॉमर्स

समैरा कोहली
96%, कॉमर्स

शौर्य सुयाल
96%, कॉमर्स

सुहानी कालरा
96%, कॉमर्स

कृष्णा कोहली
96%, कॉमर्स

कीर्ति गोयल
94.25%, कॉमर्स

## द इंडियन पब्लिक स्कूल

### सीबीएसई कक्षा 10वीं

भव्यश्री कुमारी, 99.2%

प्रियांशु कुमार, 96.6%

आर्यन कुमार गुप्ता, 95%

समीर कुमार शाह, 93.2%

नफिशा परवीन, 93.2%

जोआना कैमरन नेट्टो
92.6%

### सीबीएसई कक्षा 12वीं

आर्य आदित्य प्रसाद, 95.4%

कुमार पंचम सिंह, 94.8%

कार्तिक सुराना, 93.8%

आयुष राज, 93%

राजा बाबू, 92.8%

## सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट: कक्षा 10वीं

### चिल्ड्रन्स अकेडमी

कुशाग्र पंत, 98%

निशांत रावत, 97%

आदित्य तिवारी, 95%

तनिष्क आहूजा, 95%

उत्कर्ष बेलवाल, 94.4%

आशुतोष मलखान, 94%

इनाया तारिक, 94%

आन्या, 93%

मेहुल सेठी, 92%

## सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट: कक्षा 12वीं

### चिल्ड्रन्स अकेडमी

दिव्यांशु, 92%

अभिषेक रमन सिंह, 89%

कृष्णा साहनी, 89%

कुश कुमार, 89%

आयुषी रौतेला, 89%

# एसजीआरआर एजुकेशन मिशन के अंतर्गत संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं में लगेगी संस्कृत में नाम पट्टिकाः मंहत देवेन्द्र दास

श्री गुरु राम राय दरबार साहिब देहरादून में दीपक कुमार गैरोला- सचिव, संस्कृत शिक्षा, जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, उत्तराखंड शासन ने महंत देवेंद्र दास जी महाराज से भेंट कर कई महत्पूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। साथ ही साथ उन्हें उत्तराखंड सरकार के 'कार्यक्रम क्रियान्वयन' विभाग द्वारा प्रकाशित 'मेरी योजना' पुस्तकें भेंट कर सरकार की योजनाओं को 'दरबार साहिब' एवं 'गुरु राम राय एजुकेशनल ट्रस्ट' के माध्यम से भी प्रचारित-प्रसारित करने का अनुरोध किया।

जैसा कि विदित है कि उत्तराखंड शासन में जब से संस्कृत शिक्षा विभाग में सचिव का दायित्व दीपक कुमार गैरोला ने संभाला है तब से वह लगातार प्रदेश में द्वितीय राजभाषा संस्कृत की अवसंरचना एवं उसके क्रमिक विकास को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं, इसी क्रम में सचिव दीपक गैरोला ने महंत देवेंद्र दास जी महाराज से भेंट की जिसमें निम्न विषयों को लेकर सार्थक चर्चा और भविष्य में विभिन्न अनुबंध किये जाने पर चर्चा हुई।

1-श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के अंतर्गत संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं में लगेगी संस्कृत में नाम पट्टिका। 2-महंत इंद्रेश अस्पताल के नाम के साथ-साथ उसके अंतर्गत विभागों/चिकित्सकों का नाम भी शीघ्र संस्कृत में लिखा हुआ दिखेगा। उपरोक्त हेतु उत्तराखंड संस्कृत अकादमी अनुवाद करने में सहयोग प्रदान करेगी। 3-अब उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध एवं सबसे बड़े महंत इंद्रेश अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा के साथ बनेगा मंत्र चिकित्सा केंद्र- गहन रोगियों के मरीजों पर वेद मंत्रों यथा महामृत्युंजय जाप, गायत्री मंत्र एवं दुर्गासप्तशती में अवस्थित देवी कवचम तथा अन्य वैदिक मंत्रों के माध्यम से भी क्रियात्मक अनुसंधान कर उपचार किया जायेगा। 4- दरबार साहिब द्वारा संचालित संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों/शिक्षकों के साथ-साथ उपरोक्त अनुसंधान हेतु यदि अन्य संस्थाएँ, विद्यार्थी, शिक्षक भी आगे आना चाहते हैं तो दरबार साहिब द्वारा अपेक्षित सहयोग किया जायेगा। 5.संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं संस्कृत अकादमी तथा एसजीआरआर एजुकेशन ट्रस्ट के मध्य एमओयू की भी कार्यवाही की जायेगी जिससे द्वितीय राजभाषा के विकास, उत्थान, प्रचार-प्रसार एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

# विश्वविद्यालय मिलकर साझा नवाचार केंद्र की स्थापना करें: राज्यपाल

शुक्रवार को राजभवन में उत्तराखण्ड के स्ववित्तपोषित (निजी) विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपेक्षा की कि वे उत्तराखण्ड के मोटे अनाजों (मिलेट्स) के क्षेत्र में, यहां पर उत्पादित शहद के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में और स्वयं सहायता समूहों को सहयोग के साथ-साथ पलायन को रोकने हेतु शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से सहयोग करें।

इस अवसर सभी स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यत: प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए किए गए प्रयासों, विश्वविद्यालयों की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश के राजकीय विभागों को सहयोग, विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी किये जा रहे नवाचारों, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे शोध एवं प्रकाशन की स्थिति एवं राजभवन के 'एक विश्वविद्यालय-एक शोध' कार्यक्रम के अंतर्गत की गई प्रगति के विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

बैठक में राज्यपाल ने कहा कि इस संवाद का मुख्य उद्देश्य राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त, समावेशी एवं तकनीकी रूप से समकालीन बनाना है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल शिक्षण-प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि विश्वविद्यालय समाज व राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम भी हैं और उन्हें उम्मीद है कि उत्तराखण्ड के सभी स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय राज्य की युवा ऊर्जा को सही दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय नि:संदेह गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा को रोजगारपरक बनाकर इस क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि सभी विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को महत्व देने के साथ ही बच्चों को इस ओर प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा तथा क्वांटम जैसी नवीन तकनीकों को अपनाकर उसमें शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना समय की मांग है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है और हमारे विश्वविद्यालयों को भी इस क्षेत्र में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए। राज्यपाल ने इन क्षेत्रों में अनुसंधान, कोर्स डेवेलपमेंट और इंडस्ट्री- अकेडमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में राज्यपाल ने उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय और आपसी सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को एक-दूसरे के संसाधनों, विशेषज्ञता और नवाचार क्षमताओं को साझा करने की आवश्यकता है, जिससे उत्तराखण्ड न केवल शैक्षिक दृष्टि से अग्रणी बने बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में योगदान कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय मिलकर रिसर्च कंसोर्टियम या साझा नवाचार केंद्र की स्थापना करें, ताकि राज्य में तकनीकी स्टार्टअप और नवाचार की संस्कृति को मजबूती मिल सके और इस सुझाव का स्वागत करते हुए सभी स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा इस पहल हेतु अपना पूर्ण समर्थन देने हेतु सहमति व्यक्त की।

बैठक में कुलपतियों द्वारा प्रमुख पाँच बिंदुओं पर प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ उनके विश्वविद्यालय में अपनायी जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेज, उपलब्धियों व अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य के विकास हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं शोध पर जानकारी दी। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस बैठक में सचिव श्री राज्यपाल रविनाथ रामन, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत सिन्हा, विधि परामर्शी श्री राज्यपाल श्री अमित कुमार सिरोही के अलावा निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रतिनिधि एवं राजभवन के अधिकारी उपस्थित रहे।

# हमें सुनिश्चित करना होगा कि बाजार में उपलब्ध हर दवा सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक मानकों पर खरी उतरे- डॉ आर राजेश कुमार

## उत्तराखण्ड में दवा नियंत्रण प्रणाली को तकनीक और गुणवत्ता से जोड़ने की पहल

## राज्यस्तरीय कार्यशाला में नियामक सुधार, तकनीकी नवाचार और क्षमता निर्माण पर हुआ मंथन

राजधानी देहरादून स्थित खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन (FDA) के कार्यालय में शनिवार को औषधि नियमन प्रणाली को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने और अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

इस कार्यशाला का आयोजन ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स (आई) वेलफेयर एसोसिएशन और डीसीजीआई डब्ल्यूयू उत्तराखंड चैप्टर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में औषधि नियमन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता की।

कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड शासन के सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) व आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, 'आज के समय में दवाओं की गुणवत्ता केवल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास से भी जुड़ी है। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि बाजार में उपलब्ध हर दवा सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक मानकों पर खरी उतरे। नियामक अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षित करना और तकनीकी दृष्टि से सशक्त करना इस दिशा में अत्यंत आवश्यक कदम है।'

कार्यशाला में अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य एवं औषधि) ताजदार सिंह जग्गी, पूर्व एफडीए नियंत्रक (हरियाणा) एन.के. आहूजा, डीसीजीआई (आईडब्ल्यूयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोठेवर राव, महासचिव बलेन्द्र चौधरी और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।

**अधिकारियों को तकनीकी अपडेट रहना अनिवार्य- कोठेवर राव**

मुख्य वक्ता कोठेवर राव ने औषधि नियमन की मौजूदा चुनौतियों और डीसीजीआई (आईडब्ल्यूयू) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, 'दवा नियंत्रण अधिकारियों को विधिक प्रावधानों के साथ-साथ तकनीकी नवाचारों से भी अपडेट रहना चाहिए, ताकि वे प्रभावी नियमन सुनिश्चित कर सकें।'

**जीएमपी विश्लेषण और लेबलिंग पर व्यावहारिक सत्र- एन.के. आहूजा**

पूर्व एफडीए नियंत्रक एन.के. आहूजा ने दवाओं के नमूना विश्लेषण, जीएमपी (गुड मैन्यफुैक्चरिंग प्रैक्टिस) और लेबलिंग मानकों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों को लेबलिंग से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया।

**'उत्तराखंड में नियामन प्रणाली को पारदर्शी और परिणाममुखी बनाएंगे'- ताजबर सिंह जग्गी**

अपर आयुक्त (खाद्य एवं औषधि) ताजदार सिंह जग्गी ने कहा, 'हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड में औषधि नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए। इस दिशा में विभाग, उद्योग और विशेषज्ञों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग अत्यंत आवश्यक है।'

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ औषधि निरीक्षक नीरज कुमार ने किया। कार्यशाला का समापन आभार ज्ञापन के साथ हुआ

# जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

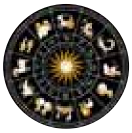
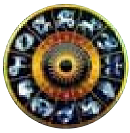

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

**मेष राशि-** विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर घर में कुछ सुधार की सोच रहे हैं, तो वास्तु के नियमों का पालन करना अच्छा रहेगा। मजेदार और जानकारी भरी किताबें पढ़ने से नई बातें जानने को मिलेंगी। बेकार की बातों और कामों में समय बर्बाद न करें, बल्कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें।

**वृषभ राशि-** अपनी दिनचर्या को सही रखकर आप ज्यादातर जरूरी काम समय पर पूरे कर लेंगे और दूसरी गतिविधियों में भी शामिल होंगे। खासकर महिलाएं खुद को साबित करने में कामयाब रहेंगी। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के झगड़े से खुद को दूर रखें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं।

**मिथुन राशि-** किसी समारोह में शामिल होने का न्योता मिलेगा, आपस में मिलने जुलने से सबको खुशी भी मिलेगी। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ किसी झगड़े जैसी बात में फंसने से अनबन हो सकती है, लेकिन समझदारी से काम लेने से जल्दी ही गलतफहमियां दूर भी हो जाएंगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उन्हें निभाना आपके लिए चुनौती होगा।

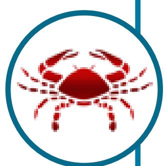

**कर्क राशि-** इस समय अपने लक्ष्य को पाना आपकी पहली सोच होगी और सफलता भी मिलेगी। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिलेगा। रिश्तों को मजबूत बनाने में आपका खास साथ रहेगा। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, तो थकान होगी, लेकिन फायदा भी होगा। पड़ोसियों के साथ किसी भी बात को लेकर न उलझें। इससे आपके सम्मान पर बुरा असर पड़ सकता है।

**सिंह राशि-** हालात में अच्छा बदलाव हो रहा है। आप अपनी मेहनत से अपनी सफलताएं हासिल कर लेंगे। युवा वर्ग भी आलस छोड़कर पूरे मन से अपने लक्ष्य को पूरा करें, निश्चित ही अच्छी सफलता मिलेगी। परिवार या समाज की समस्याओं में व्यस्त रहने से आपके अपने काम अधूरे भी रह सकते हैं। इस समय पैसों की स्थिति में कुछ परेशानी आएगी, लेकिन चिंता न करें।

**कन्या राशि-** अपनी काबिलियत से उम्मीद से ज्यादा फायदा हासिल करने वाले हैं। व्यस्त रहने के बावजूद कुछ समय घर परिवार और रिश्तेदारों के साथ बिताना आपको ताजगी देगा। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से राहत मिलेगी। किसी भी हालात में अपने गुस्से पर काबू रखें। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ झगड़े में फंसने से माहौल खराब हो सकता है।

**तुला राशि-** अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। मुश्किल से मुश्किल काम में आप अपने पक्के इरादे से पूरा करने की ताकत रखेंगे। कहीं पैसे लगाने का सोच रहे हैं, तो तुरंत करें। घर से जुड़े कामों में भी कुछ समय बीतेगा। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है। फोन या दोस्तों के साथ घूमने में अपना समय बर्बाद न करें।

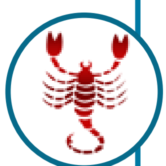

**वृश्चिक राशि-** व्यस्त रहने के बावजूद अपनी रचनात्मक रुचियों को भी बनाए रखें। इससे मन खुश और ऊर्जावान बना रहेगा। बच्चों के भविष्य को लेकर जरूरी योजनाएं बनेंगी और पैसे लगाने से जुड़े काम भी पूरे होंगे, जो फायदेमंद रहेंगे। ध्यान रखें कि ज्यादा सोचने के कारण कई जरूरी काम छूट जाएंगे। किसी भी खास काम में परिवार के सदस्यों की भी सलाह लेना जरूरी है।

**धनु राशि-** आपको अपनी मेहनत के मुताबिक अच्छा फल मिलेगा। संतान द्वारा कोई अच्छी खबर मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए कोई रिश्ता आने की उम्मीद है। लापरवाही और आलस जैसी कमियों को दूर करने की कोशिश करें, नहीं तो आपके काम रुकेंगे। किसी भी काम को टालने की बजाय समय पर पूरा करें।

**मकर राशि-** अचानक ही कोई रुकी हुई पेमेंट आने से या कोई खास काम बन जाने से आप तनाव कम महसूस करेंगे। दिल की बजाय दिमाग की बात को अहमियत दें। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ चल रहे खराब रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। विद्यार्थी बेकार की मौज मस्ती में समय न दें। किसी की नेगेटिव बात पर गुस्सा होने की बजाय शांति से समस्या का हल निकालें।

**कुंभ राशि-** कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना और योजना बनाना आपको निश्चित ही सफल करेगा। अपनी किसी कमजोरी पर भी काबू पाने में कामयाब रहेंगे। करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलने जुलने से खास बातों पर बातचीत भी होगी। संतान की कोई नेगेटिव हरकत पता चलने से चिंता रहेगी, लेकिन आपकी समझदारी से समस्या का हल भी निकल जाएगा।

**मीन राशि-** आपकी काबिलियत लोगों के सामने साफ दिखेगी, इसलिए लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक कामों पर ही ध्यान दें। पहले तो बातें उठेंगी, लेकिन आपको सफलता मिलने से यही लोग आपके पक्ष में हो जाएंगे। कभी-कभी कुछ मुश्किल हालात भी बनेंगे। पैसों के मामलों में और ज्यादा सोचना विचारना जरूरी है।

# बॉलीवुड में 'ऑपरेशन सिंदूर' बनाने के लिए खींचतान, फिल्म मेकर्स आपस में भिड़े

**पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने को लेकर बॉलीवुड के डायरेक्टर आपस में भिड़ रहे हैं। दर्जनों शीर्षक (टाइटल) के लिए कई आवेदन किए गए हैं। सभी कह रहे हैं 'मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा।' खास बात यह है कि मेकर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत ज्यादा न समझा है न रिसर्च किया लेकिन फिर भी फिल्म बनाने के लिए ठान ली है। बॉलीवुड में यह चलन नया नहीं है, जब भी देश में कोई बड़ा सैन्य अभियान या राष्ट्रीय घटना होती है, तो निर्माता सबसे पहले उससे जुड़े टाइटल को खरीदने में लग जाते हैं। हालांकि कई बार ये टाइटल केवल भविष्य की संभावनाओं के लिए बुक किए जाते हैं, भले ही उस पर फिल्म बने या नहीं। सेना के इस सफल ऑपरेशन के बाद फिल्म मेकर्स ने पोस्टर भी जारी कर दिया, जिसमें एक महिला सिपाही को, वर्दी में अपने माथे पर सिंदूर लगाते देखा जा सकता था। पोस्टर के बैकग्राउंड में युद्ध जैसी पृष्ठभूमि दिखाई गई थी।**

दुनिया कितनी व्यवसायिक (प्रोफेशनल) है हर चीज में अपना फायदा देखती है। इन दिनों बॉलीवुड में 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर फिल्म बनाने के लिए मारामारी मची है। वर्तमान समय में निर्माता, निर्देशकों के पास कोई अच्छा विषय रह नहीं गया है। ऐसे में बॉलीवुड को इन दिनों हॉट सब्जेक्ट ऑपरेशन सिंदूर पर ही फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर आपस में ही भिड़ रहे हैं। दर्जनों शीर्षक (टाइटल) के लिए कई आवेदन किए गए हैं। सभी कह रहे हैं 'मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा।' सबसे खास बात यह है कि फिल्म मेकर्स ने ऑपरेशन

सिंदूर को लेकर बहुत ज्यादा न समझा है न रिसर्च किया लेकिन फिर भी फिल्म बनाने के लिए ठान ली है। बता दें कि बॉलीवुड में यह चलन नया नहीं है। जब भी देश में कोई बड़ा सैन्य अभियान या राष्ट्रीय घटना होती है, तो निर्माता सबसे पहले उससे जुड़े टाइटल को खरीदने में लग जाते हैं। हालांकि कई बार ये टाइटल केवल भविष्य की संभावनाओं के लिए बुक किए जाते हैं, भले ही उस पर फिल्म बने या नहीं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। सेना के इस सफल ऑपरेशन के बाद बॉलीवुड में इस टाइटल और इस पर फिल्म बनाने की होड़ मच गई। भगनानी फिल्म्स नाम की कंपनी ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म का भी एलान कर दिया, जिसे जैकी भगनानी के कजन ब्रदर विकी भगनानी प्रोड्यूस कर रहे हैं और डायरेक्शन उत्तम महेश्वरी और नितिन कुमार गुप्ता मिलकर रहे हैं। इस ऐलान के साथ ही एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें एक महिला सिपाही को, वर्दी में अपने माथे पर सिंदूर लगाते देखा जा सकता था। पोस्टर के बैकग्राउंड में युद्ध जैसी पृष्ठभूमि दिखाई गई थी। मेकर्स ने जैसे ही पोस्टर जारी किया, सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद फिल्म मेकर्स को माफी मांगनी पड़ी। डायरेक्टर ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्र के लिए सम्मान और प्यार के कारण बनाई गई है न कि फेमस होने और पैसा कमाने। हालांकि ये समय सही नहीं था, इसके लिए मुझे खेद है। उन्होंने कहा, यह केवल एक फिल्म नहीं है, यह पूरे देश की भावना और वैश्विक स्तर पर देश की एक सामाजिक छवि है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए उनको धन्यवाद भी दिया। अंत में उन्होंने कहा कि हमारा प्यार और प्रार्थना हमेशा शहीद परिवारों के साथ रहेगी, जो हमारे लिए दिन और रात सीमा पर लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस होने लगी कि इस फिल्म में रोल अक्षय कुमार निभाएंगे या फिर विक्की कौशल? भारतीय सेना के इस साहसिक ऑपरेशन पर फिल्म बनाने के लिए अक्षय कुमार और विक्की कौशल आपस में भिड़ गए। हालांकि बाद में अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने सफाई दी कि ऐसी कोई बात नहीं थी।

**ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े 30 से अधिक शीर्षक पंजीकृत कराने के लिए आवेदन दिए गए**

भारत की ओर से पाकिस्तान एवं पीओके में किए गए सैन्य हमलों के बाद बॉलीवुड में 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़े फिल्म शीर्षक के लिए आवेदन करने की होड़ मच गई है। फिल्म निर्माताओं ने महज दो दिन में 30 से अधिक शीर्षक पंजीकृत कराने के लिए आवेदन दे दिए हैं। पंजीकरण के लिए दिए गए आवेदनों में ऑपरेशन सिंदूर, मिशन सिंदूर और सिंदूर, द रेवेंज सहित अन्य शीर्षक शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा मुरीदके शामिल हैं। भारतीय मोशन पिक्चर प्रोडयूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए), भारतीय फिल्म और टेलीविजन प्रोडयूसर्स काउंसिल (आईएफटीपीसी) और वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोडयूसर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूआईएफपीए) को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े फिल्म शीर्षक के पंजीकरण के लिए ढेरों आवेदन मिले हैं।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

# BADRI COW GHEE

पारंपरिक बिलौना विधि द्वारा तैयार

औषधीय गुणों से परिपूर्ण

इम्यूनिटी एवं स्मरण शक्ति बढ़ाने में लाभदायक

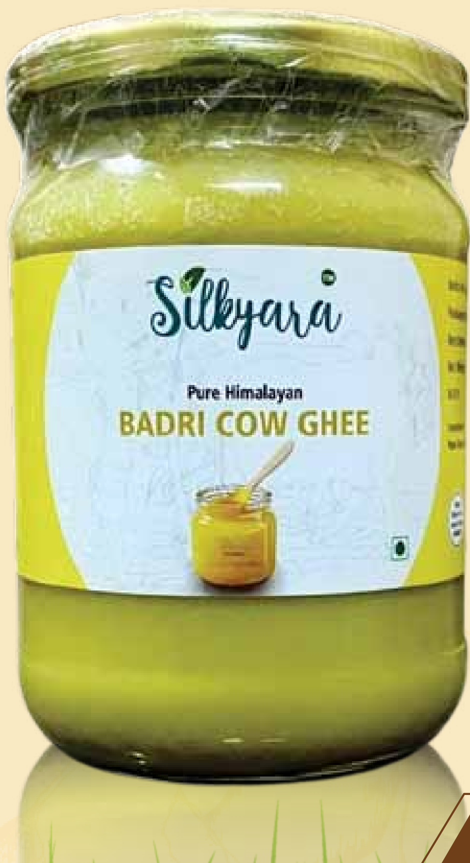


विटामिन्स से भरपूर

सभी प्रकार के खाना पकाने के लिए आदर्श

## कुमार स्वीट्स

सहस्त्रधारा रोड पर उपलब्ध

## उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र का बना दुर्लभ घी

fssai
22623030001586

UDYOG AADHAR
AADHAAR
MSME
UK050061483

Call or Whatsapp
7409782771